

an>

title: The Minister of Parliamentary Affairs made a statement regarding Government Business during the week commencing the 8th August, 2016 and submissions made by Members.

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): With your permission, Madam, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 8th of August, 2016 will consist of:-

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper.
2. Consideration and passing of the following Bills:-
 - (a) The Citizenship (Amendment) Bill, 2016;
 - (b) The High Courts (Alteration of Names) Bill, 2016;
 - (c) The Central Agricultural University (Amendment) Bill, 2016;
 - (d) The Employee's Compensation (Amendment) Bill, 2016.
3. Consideration and agreeing to the amendments made by Rajya Sabha in the Enemy Property (Amendment and Validation) Bill, 2016, as passed by Lok Sabha, after it is passed by Rajya Sabha – To replace an Ordinance
4. Consideration and passing of the Mental Health Care Bill, 2013, after it is passed by Rajya Sabha.
5. Consideration and agreeing to the amendments made by Rajya Sabha in the Constitution (One Hundred and Twenty Second Amendment) Bill, 2016 as passed by Lok Sabha and as reported by the Select Committee of Rajya Sabha.

श्री गोपाल शेठी (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष महोदया, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नांकित दो विषयों को सम्मिलित किया जाये :--

1. केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जे.एन.एन.यू.आर.एम. मिशन के अन्तर्गत राज्य सरकारों को शहरी स्थानीय निकायों की मदद के उद्देश्य से शहरी बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने दिए जाने हेतु निधि का आबंटन किया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने जे.एन.एन.यू.आर.एम. मिशन के अन्तर्गत जो प्रस्ताव प्रेषित किया है, उस पर शीघ्र कार्यवाही करते हुए राज्य सरकार को धन का आबंटन किए जाने से संबंधित विषय।
2. महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय को सूचित किया था कि "उच्च न्यायालय बम्बई" का नाम "उच्च न्यायालय मुंबई" किए जाने में उसको कोई आपत्ति नहीं है। तत्पश्चात् केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने 27.8.2012 में अवगत कराया कि मंत्रालय ने बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास उच्च न्यायालयों के नाम परिवर्तित किए जाने हेतु विधायी प्रस्ताव प्रेषित किये हैं।

"उच्च न्यायालय मुंबई" का नाम "उच्च न्यायालय मुंबई" किए जाने से संबंधित विषय।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : अध्यक्ष महोदया, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्न विषय को जोड़ने की कृपा की जाये :--

1. मेरे संसदीय क्षेत्र गिरिडीह में केन्द्रीय विद्यालय शुरू करने की योजना लगभग पांच वर्षों से लंबित है। मेरा आपसे आग्रह है कि मेरे गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय अविलंब स्थापित किया जाये।
2. बोकारो जिला के अंतर्गत प्रखण्ड नवाडीह, कसमार, जरीडीह, गोमिया में हाथियों के उत्पात से जान-माल की सुरक्षा और मुआवज़े की व्यवस्था की जाए। जो फसल का नुकसान हुआ, उसके लिए किसानों को मुआवज़ा मिले एवं हाथियों द्वारा जिनके घर तोड़े गये, उन्हें इंदिरा आवास या प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराये जायें।

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदया, बिहार राज्य में गंगा के किनारे-किनारे आदिवासियों की तरह आदम युग से ज़िंदगी जीने वाले तथा शैक्षणिक और आर्थिक रूप से अति पिछड़ी गंगोता जाति को आज तक आरक्षण का सही दर्जा नहीं मिल पाया है। इस जाति को अनुसूचित जन-जाति में शामिल कर अधिसूचित किये जाने की आवश्यकता के संबंध में।

बिहार राज्य के भागलपुर के सुल्तानगंज से शुरू होकर झारखंड राज्य के देवघर तक लगभग 100 किलोमीटर तक के पैदल कांवड़ यात्रा के श्रवणी मेले को राष्ट्रीय मेला घोषित किये जाने की आवश्यकता के संबंध में।

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Madam, I hereby request you to include the following in the List of Business for next week of the Monsoon Session of the Parliament:

- (a) There is no direct rail commutation option available for passengers traveling from Balasore to Mumbai. Any passenger traveling on that route needs to travel up to Bhubaneswar or Kharagpur. As thousands of people commute on that route, I put forth my request to run a train between Balasore and Mumbai, at least on a weekly basis to start immediately, ensuing better connectivity for the

passengers.

- (b) The objective of the Skill Development Mission is to create an end-to-end implementation framework for skill development. However, because of the unethical practices of the Skill Development Implementation Agencies in the States, the sole purpose of the Mission is getting defeated. It is observed in a number of cases that the funds released by the centre to the accounts of beneficiaries for their skill upgradation is being transferred to the private bank accounts of the implementing agencies. Hence, I request this issue to be inserted in the List of Business for the next week for detailed discussion.

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए:

1. भारत की सीमा से सटे चार किलोमीटर नेपाल के नो मैस लैंड में खाये, मोहली, जीता एवं तिलचुवा, ये चार नदियां बढ़ती हैं। इन चारों को मिलाते हुए, उनके गढ़ को तीन मीटर गहराई से निकालकर और नदी की दस मीटर चौड़ाई बढ़ा देने से इस बाढ़ की समस्या का समाधान निकल सकता है। अतः भारत सरकार को नेपाल सरकार से अविलम्ब वार्ता कर, इस कार्य को सुदृढ़तर पर करवाने की आवश्यकता है।
2. सरकार द्वारा देश भर में अच्छी एवं सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देश के प्रत्येक जिले में कस्तूरबा गांधी एवं नवोदय विद्यालय की स्थापना की गयी है, जिससे आम गरीब लोगों के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकें, लेकिन इन विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ विस्तार की भी आवश्यकता है। अतः कस्तूरबा गांधी एवं नवोदय विद्यालय को देशभर में पूखण्ड स्तर पर खोलने हेतु सख्त नियम बनाया जाए।

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में दो विषयों को शामिल किया जाए। इस समय पूरे देश में जगह-जगह दलित उत्पीड़न हो रहा है, चाहे कल पटना में विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज हुआ, मैनेपुरी में 15 रुपये के खातिर ऐसी घटना हुई और तमिलनाडु, केरल एवं गुजरात आदि राज्यों में जो दलितों का उत्पीड़न हुआ है, उस पर चर्चा हो।

मेरी दूसरी मांग है कि कज्जकूमर प्राइस इंडेक्स है, वास्तव में वर्ष 2014 की तुलना में, अप्रैल 2015 में महंगाई घटी है। सरकार की ओर से तमाम प्रयास हुए हैं, लेकिन एक गलत मैसैज देने का प्रयास किया जा रहा है। इसको भी शामिल करने की कृपा की जाए। धन्यवाद।

डॉ. वीरेंद्र कुमार (टीकमगढ़) : अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए:

1. मेरे संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ में स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा हॉकी प्रशिक्षण केन्द्र प्रारम्भ किया गया है। वहां पर इनडोर ग्रेस के लिए हॉल भी बनवाए गए तथा मैदान भी हैं, परन्तु बाहर से आने वाले खिलाड़ियों के लिए छात्रावास की सुविधा नहीं है। अतः देश के सभी क्रीड़ा स्थलों के साथ ही टीकमगढ़ में भी खिलाड़ियों के लिए छात्रावास भवन निर्माण कराने हेतु खेल प्राधिकरण से राशि दिलाए जाने की आवश्यकता है।
2. मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स उपलब्ध हैं। खनन का कार्य केवल निजी क्षेत्र के सम्पन्न लोगों द्वारा ही किया जा रहा है। ग्रेनाइट यहां से बड़ी मात्रा में कांडला बंदरगाह से होकर विदेशों में जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा वहां पर प्लांट लगाकर क्षेत्र के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए:

1. बिहार में दलित, मुसलमान एवं अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के बच्चों के शैक्षणिक विकास एवं कल्याण हेतु प्रत्येक जिले में दलित, मुसलमान एवं अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास खोले गए थे, जिनकी स्थिति काफी जर्जर है एवं ये छात्रावास रहने के लायक नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में इस छात्रावासों की मरम्मत के साथ-साथ प्रत्येक प्रखंड में पांच-पांच दलित, मुसलमान एवं अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास का निर्माण करने हेतु सख्त नियम बनाया जाए।
2. भोजन, पेय पदार्थ, दवाइयों और अन्य उपयोगी पदार्थों की पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक के उपयोग की सुविधा अब इंसान के अस्तित्व के लिए खतरा बन गयी है। नॉन-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से संग्रहित सामग्री, मिट्टी और पानी में हानिकारक रसायनों और भारी धातुओं का रिसाव करता है, जो कैंसर, जन्म-दोष, टाइप-2 मधुमेह, श्वसन और हृदय की बीमारियों का कारण बनता है, जो कि स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा है। अतः प्लास्टिक उत्पादों की पूर्ण बंदी हेतु सख्त नियम बनाया जाए।

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र के लोक महत्व के निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किया जाए।

मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर के मुसाबनी प्रखंड के अंतर्गत सखा, चापड़ी और केन्दाड़ीह माइंस हैं। ये तीनों माइंस वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अनापति प्रमाण-पत्र नहीं मिलने के कारण चालू नहीं हो पा रही हैं। ये क्षेत्र आदिवासी, अतिपिछड़े, जनजातीय बाहुल्य एवं उन्मुक्त प्रभावित हैं। यहां के लोग सुखाड़, बेरोजगारी और गरीबी के कारण पलायन करने को मजबूर हैं, इसलिए केन्द्र सरकार से मेरी मांग है कि अविलम्ब अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर माइंस को चालू करवाने की कृपा की जाए।

जमशेदपुर (झारखंड) का ग्रामीण क्षेत्र कृषि पर ही आश्रित है, लेकिन सिंचाई का समुचित साधन नहीं होने के कारण यहां के किसानों को खेती करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए केन्द्र सरकार से मांग करते हैं कि अविलम्ब नींदीह प्रखंड में एक नई नहर का निर्माण करवाया जाए। ये नहर मुंडु घाट से शुरू होते हुए लावा घाट, देबन घाट होते हुए पड़ोसी प्रखंड बोडा, पटमदा, कांठिन होते हुए पश्चिम बंगाल की सीमा तक जाएगी। धन्यवाद।

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण (दिंडोरी) : माननीय अध्यक्ष जी, अगले सप्ताह की लोक सभा की कार्यवाही के लिए निम्नलिखित विषय को एजेंडा में जोड़ा जाए। यह विषय मेरे पिछड़े क्षेत्र के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

रेल नीर मध्य रेलवे के सभी रेलवे स्टेशंस पर उपलब्ध नहीं है। अगर रेल नीर का उत्पादन कम हो रहा है तो उसके नये प्लांट मध्य रेलवे के नासिक जिले के मेरे संसदीय क्षेत्र दिंडोरी में लगाया जाने का कार्य किया जाए क्योंकि प्राकृतिक रूप से यहां का पानी बहुत ही शुद्ध है।

मेरे संसदीय क्षेत्र दिंडोरी के मांजर पाडा प्रकल्प एक का सवा आठ किलोमीटर कार्य पूरा हो गया है किंतु महत्वपूर्ण पौने कि.मी. का कार्य अभी होना बाकी है, जिसकी वजह से इस टनल के अभी तक पूरा नहीं होने के कारण दिंडोरी, निफाड, चांदवड येवला एवं नांदगांव में खेती और पेयजल की काफी किलत हो रही है। इस परियोजना को केन्द्र स्तर पर सहायता एवं आर्थिक मदद देकर

पूरा किया जाने का काम करया जाए। धन्यवाद।